

CORRIGENDUM

No. 450/S.E. Chandigarh, Circle Hr P.W.D. B.&R. Br., Chandigarh.—The notification under section VI for constructing road from Khizrabad to Khizri in Ambala District were published in *Haryana Government Gazette*,—vide notification No. SE/PWD/B&R/Chandigarh 435R, dated 15th October, 1984 on 30th October, 1984 at page No. 1635-1636.

There was omission in printing in the press and following correction may be read for the figures given below :—

Name of Village	District	H. No.	Khasra No.	May be read
Khizrabad	Ambala	100	69/1	Omission in printing 69/1

(Sd.)

Superintending Engineer,

Chandigarh Circle, Hr. P.W.D., B. & R. Branch,
Chandigarh.

श्रम विभाग

दिनांक 21 दिसम्बर, 1984

सं० ओ० वि०/यमुना/64-84/44847. —चूँकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैं परिवहन आयुक्त, हरियाणा, चण्डीगढ़, 2. महा प्रबन्धक, हरियाणा राज्य परिवहन, यमुना नगर, के श्रमिक श्री सुन्दर लाल ड्राईवर तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूँकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं० 3(44)-84-3-श्रम, दिनांक 10 अप्रैल, 1984 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, अम्बाला को विवादग्रस्त या उससे संबंधित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय के लिये निर्दिष्ट करते हैं, जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा संबंधित मामला है :—

क्या श्री सुन्दर लाल ड्राईवर की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं० ओ० वि०/यमुना/100-84/44854.—चूँकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैं लाम्बा इंटर प्राईजिज, बुड़िया गेट, जगाधरी, के श्रमिक श्री सहीद हसन तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूँकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उप-धारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं० 3(44)84-3-श्रम, दिनांक 10 अप्रैल, 1984 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, अम्बाला को विवादग्रस्त या उससे संबंधित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय के लिए निर्दिष्ट करते हैं, जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा संबंधित मामला है :—

क्या श्री सहीद हसन की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

बी. पी. सहगल,

संयुक्त सचिव, हरियाणा सरकार,
श्रम विभाग।